भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *53
उत्तर देने की तारीख 23 जुलाई, 2026

दूरसंचार उपकरणों का मूल्य संवर्धन

53 #श्री नीरज डांगी:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में दूरसंचार उपकरणों में मूल्य संवर्धन करने के लिए क्या विशेष उपाय किए जा रहे हैं;
(ख) भारतीय और वैश्विक कंपनियों को दिए गए लाभों का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;
(ग) कितनी कंपनियों ने अपने निवेश और उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त किया है; और
(घ) भविष्य में भारत को दूरसंचार उपकरण विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने संबंधी सरकार की रणनीति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

***

"दूरसंचार उपकरणों का मूल्य संवर्धन" विषय पर दिनांक 23 जुलाई, 2026 के राज्यसभा तारांकित प्रश्न संख्या 53 के भाग (क) से (घ) के संबंध में राज्य सभा के पटल पर रखा जाने वाला विवरण

(क)से(घ): दूरसंचार विभाग ने स्कीमों के शुभारंभ के माध्यम से घरेलू विनिर्माण ईकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए कई उपाय किए हैं, जो दूरसंचार उपकरणों के स्थानीय मूल्यवर्धन में वृद्धि करने में सक्षम बनाएंगे और भारत को एक वैश्विक दूरसंचार उपकरण विनिर्माण केंद्र बनाने में मदद करेंगे। भारतीय और विदेशी कंपनियों को दिए गए लाभ, अनुमोदित कंपनियों की संख्या और उनकी अंतर्निहित कार्यनीति सहित उक्त स्कीमों का विवरण इस प्रकार है:

(i) *दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम:* यह स्कीम वृद्धिशील निवेश और बिक्री को प्रोत्साहित करके भारत में दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 12,195 करोड़ रु के परिव्यय के साथ शुरू की गई है। यह स्कीम भारत में डिजाइन किए गए दूरसंचार उत्पादों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन आधारित विनिर्माण के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन भी प्रदान करती है, जिससे उच्च स्थानीय मूल्यवर्धन को बढ़ावा दिया जा सके। इस स्कीम के तहत प्रोत्साहन का लाभ, स्कीम के तहत अनुमोदित सभी पात्र कंपनियों, चाहे वे भारतीय हों या विदेशी कंपनियां हों, द्वारा उठाया जा सकता है। इस स्कीम के तहत कुल 42 कंपनियों को अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिनमें से 26 कंपनियाँ अपने परियोजित संचयी निवेश और 11 कंपनियाँ अपनी परियोजित संचयी बिक्री से आगे बढ़ गइ हैं। दिनांक 30.6.2026 तक, इस स्कीम से 5,627 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है, कुल 1,20,721 करोड़ रुपये की पात्र बिक्री हुई है, जिसमें 28,138 करोड़ रुपये की निर्यात बिक्री और 36,319 रोजगार सृजन शामिल है। कुल 17 भारतीय और 6 विदेशी कंपनियों ने स्कीम के तहत लागू निवेश और वृद्धिशील बिक्री शर्तों को पूरा करते हुए क्रमशः 1,616 करोड़ रुपये और 1,180 करोड़ रुपये की कुल प्रोत्साहन राशि का दावा किया है।

(ii) *दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि स्कीम:* यह स्कीम घरेलू कंपनियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), शैक्षणिक और अनुसंधान तथा विकास संस्थानों और सरकारी संस्थाओं को दूरसंचार प्रौद्योगिकियों, सॉल्यूशनों और उत्पादों और इसके व्यावसायीकरण के लिए अनुसंधान और विकास हेतु अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। दिनांक 30.6.2026 तक, पात्र भारतीय कंपनियों

को कुल 136 परियोजनाओं को अनुमोदन दिया गया है, जिसके लिए ऐसी भारतीय कंपनियों को कुल 263 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता राशि जारी की गई है। इस स्कीम के तहत विदेशी कंपनियां सहायता के लिए पात्र नहीं हैं।

(iii) *ग्वालियर, मध्य प्रदेश में दूरसंचार विनिर्माण जोन:* यह दूरसंचार विभाग और मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से दूरसंचार विनिर्माण जोन की स्थापना के लिए है, ताकि विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में विभिन्न सुविधाओं के सह-स्थान को सक्षम बनाया जा सके, जिससे लागत अक्षमताओं को कम करने में मदद मिल सके। दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र में भारतीय और विदेशी दोनों कंपनियों के लिए समान सुविधाओं की परिकल्पना की गई है।

इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने निम्नलिखित स्कीमें शुरू की हैं जो दूरसंचार उपकरणों सहित घरेलू विनिर्माण इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने में भी योगदान देती हैं, जो ऐसे उपकरणों के स्थानीय मूल्यवर्धन में वृद्धि को भी सक्षम बनाती हैं:

(i) इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ईसीएमएस) को दूरसंचार सहित सभी क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सब-असेंबली के घरेलू विनिर्माण को सहायता देने के लिए 40,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू किया गया है, जिससे स्थानीय घटकों की आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ किया जा सके।

(ii) भारत सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) को देश में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन और सेमीकंडक्टर डिजाइन इकोसिस्टम के विकास में सहायता प्रदान करने के लिए 76,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू किया गया है, जिससे दूरसंचार उपकरण निर्माण के लिए सेमीकंडक्टर घटकों की उपलब्धता में सुधार होगा।

***